(c) if so, what are the reasons for which no action was taken against him and what steps Government propose to take to thwart any attempt in future by him to stay in India illegally?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Raids at the Business Premises of Formica India Ltd., Pune

771. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that income tax authorities conducted raids at the business premises of 24 firms owned by Formica India Ltd. of Pune, at several places;

(b) whether it is a fact that during the raids several incriminating documents have been seized; and

(c) if so, what are the details in this regard and what action has been taken or is proposed to be taken by Government in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

दिल्ली में "बन्द"

772. **श्री संतोष बागडोदिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिल्ली में कितने "बन्दों" का आयोजन किया गया; और

(ख) इन बन्दों को रोकने तथा इसके फलस्वरूप आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विभिन्न राजनैतिक संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में निम्नलिखित संख्या में बन्द आयोजित किए गए :—

वर्ष	बन्दों की संख्या	पार्टी का नाम
1985	2	भारतीय जनता पार्टी
1986	4	2 सभी विपक्षी दलों द्वारा और दो भारतीय जनता पार्टी द्वारा
1987	3	2 भारतीय जनता पार्टी द्वारा और एक समाजवादी पार्टी द्वारा
1988	2	1 भारतीय जनता पार्टी और लोक दल द्वारा,
(20–7–88 तक)	1	सभी विपक्षी दलों (भारतीय जनता पार्टी और लोक दल को छोड़कर) द्वारा।

(ख) जब कभी कोई बन्द आयोजित किया जाता है तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने दुकानों और संस्थानों इत्यादि को जबरदस्ती बन्द करवाने से रोकने के लिए विस्तृत पुलिस प्रबन्ध किए जाते हैं।